

समाधान ऑनलाइन में लैंबित समस्याओं का हुआ समाधान...

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की जाएः मुख्यमंत्री

20 शासकीय सेवकों के विरुद्ध निर्देश और नोटिस जारी करने की कार्रवाई

भोपाल (काप्र)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले 20 अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल प्रदाय में अव्यवस्था के दोषी ठेकेदार को अर्थदंड से दर्दित किया गया।

शुक्रवार के समाधान ऑनलाइन में सौएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों का शास्त्रीय कार्रवाई गया जिनका लंबित समय से समाधान लंबित था। मुख्य सचिव अनुग्रह जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि ठेकेदार फर्म मेसर्स विश्व पर 37 हजार 469 की शास्त्रीय कार्रवाई गई है। नल जल योजना के क्रियावान में आर ही तकनीकी दिक्षितों को दूर कर घोलू नल केनकरणों में जलापूर्ण प्रारंभ करवा दी गई है। इसी तरह मऊगंज के शिकायतकर्ता सुनील कुमार साहू को शिकायत पर डेढ़ वर्ष से पाइप लाइन के टूट जाने से जल प्रदाय में आ रही दिक्षित को दूर कर दिया गया है। इस मामले में भी सचिव ठेकेदार के एनके कंपनी को तत्काल कार्य करवाने के निर्देश दिए गए। इस प्रकरण में परियोजना इकाई में पदस्थ फील्ड इंजीनियर की सेवाएं समाप्त की गई हैं। शिकायत का निराकरण समय पर

ऑनलाइन में शुक्रवार को पेयजल व्यवस्था से संबंधित 3 प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों को दायित करने का निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि जिले से नारिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होंगी वहाँ संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल प्रदाय में अव्यवस्था के दोषी ठेकेदार को अर्थदंड से दर्दित किया गया।

शुक्रवार के समाधान ऑनलाइन में सौएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों का शास्त्रीय कार्रवाई गया जिनका लंबित समय से समाधान लंबित था। मुख्य सचिव अनुग्रह जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समाधान ऑनलाइन में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

डॉ. यादव ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान



न करने के लिए उत्तरदायी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन के उत्तरदायी, परियोजना प्रबंधक और सहायक परियोजना प्रबंधक को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी जिलों में नल-जल योजना के क्रियान्वयन में विलंब करने वालों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा जिले की श्रीमती दुर्गावाई विश्वकर्मा द्वारा कूप निर्माण के लिए समय पर कार्रवाई न करने के मामले में जनपद के मुख्य कार्यालय अधिकारी और सहायक अंतीं को दो-दो वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताए नोटिस जारी किए गया हैं। साथ ही गंधीराम परियोजना के उप संचालक, जिला कार्यालय अधिकारी और निश्चिकता एक लाख रुपए की ग्राम विकास योजना में यह मामले आने के बाद गत 21 मार्च को कलम दंपति को एक लाख रुपए की ग्राम विकास योजना के लिए रोका गया है। इस प्रकरण में योजना के प्रभारी सहित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी और सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक, जिला कार्यालय अधिकारी और निश्चिकता को छात्रवृत्ति की राशि 22 हजार 748 रुपए का भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर दिया गया है। डॉ. यादव ने विदिशा के रोहित रैकवार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में की गई शिकायत का समाधान किया गया। आवेदक को दस हजार रुपए की राशि प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आवेदक ने जिलों में लंबित हैं, उनमें तत्काल संबंधित अधिकारी समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है। इस प्रकरण में आवेदक ने त्रैग्रन्थ नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।

आवेदिका को मिली प्रसूति सहायता

समाधान ऑनलाइन में युना जिले से मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (संबल) के अंतर्गत प्राप्ता के अनुसार प्रसूति सहायता न मिलने का आवेदन आया था। इस प्रकरण में हिताहाही को योजना की राशि प्रदान कर दी गई है। बिलंब के दोषी मेरठनीटी वार्ड इंचार्ज, मेरठनीटी विंग डाटा एंटी ऑपरेटर, तत्कालीन सीएम हेल्पलाइन डाटा एंटी ऑपरेटर, लखापाल जिला चिकित्सालय युना को 7-7 दिन के मानदेश वेतन कठीनी का दंड दिया गया। इसी तरह आरएमओ जिला चिकित्सालय युना, सिविल सजन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय युना और संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं गवालियर संभाग को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। दितिया जिले के शिकायतकर्ता रोहित ने आवेदक श्री बुद्ध सिंह द्वारा भारतीय स्टेट बैंक दितिया याशा द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण-जारी करायी रखना की शिकायत की गई है। आवेदक ने केसीसी के सभी भुगतान कर दिए गए, लेकिन बंधक प्रबंधन द्वारा तहसील में बंधक मुक्ति का पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकरण में आवेदक ने त्रैग्रन्थ नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह से परेशान होना पड़े। यह अनुचित ही नर्वी अपराध भी है। इस तरह के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों का बच्चा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में आई शिकायतों के संदर्भ में यह भी निर्देश दिए कि इस स्वरूप की व्यापारी समाधान तहसीली वहाँ निर्देश दिए।

प्रकरण यथासमय स्वीकृत करने के लिए रैकवार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में की गई शिकायत का समाधान किया गया। आवेदक को दस हजार रुपए की राशि प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आवेदक ने जिलों में देश में अग्रणी है। इस नाते योजना के क्रियान्वयन की श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवेदक का आवेदन लाग्या का आवेदन लाग्या। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिलों में देश में अग्रणी है। इस नाते योजना के क्रियान्वयन की श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवेदक का आवेदन लाग्या का आवेदन लाग्या।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह से परेशान होना पड़े। यह अनुचित ही नर्वी अपराध भी है। इस तरह के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों का बच्चा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आवेदक ने जिलों में देश में अविवाही बंधक मुक्ति प्रमाण-जारी करायी रखना की शिकायत की गई है। आवेदक ने केसीसी के सभी भुगतान कर दिए गए, लेकिन बंधक प्रबंधन द्वारा तहसील में बंधक मुक्ति का पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकरण में आवेदक ने त्रैग्रन्थ नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह से परेशान होना पड़े। यह अनुचित ही नर्वी अपराध भी है। इस तरह के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों का बच्चा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आवेदक ने जिलों में देश में अविवाही बंधक मुक्ति प्रमाण-जारी करायी रखना की शिकायत की गई है। आवेदक ने केसीसी के सभी भुगतान कर दिए गए, लेकिन बंधक प्रबंधन द्वारा तहसील में बंधक मुक्ति का पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकरण में आवेदक ने त्रैग्रन्थ नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह से परेशान होना पड़े। यह अनुचित ही नर्वी अपराध भी है। इस तरह के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों का बच्चा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आवेदक ने जिलों में देश में अविवाही बंधक मुक्ति प्रमाण-जारी करायी रखना की शिकायत की गई है। आवेदक ने केसीसी के सभी भुगतान कर दिए गए, लेकिन बंधक प्रबंधन द्वारा तहसील में बंधक मुक्ति का पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकरण में आवेदक ने त्रैग्रन्थ नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह से परेशान होना पड़े। यह अनुचित ही नर्वी अपराध भी है। इस तरह के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों का बच्चा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान आवेदक ने जिलों में देश में अविवाही बंधक मुक्ति प्रमाण-जारी करायी रखना की शिकायत की गई है। आवेदक ने केसीसी के सभी भुगतान कर दिए गए, लेकिन बंधक प्रबंधन द्वारा तहसील में बंधक मुक्ति का पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकरण में आवेदक ने त्रैग्रन्थ नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।